PERFORM INDIA
National Movement for Developed India

विश्व दिव्यांग दिवस

विशेषांक

वर्ष : 1, अंक : 3

03 दिसंबर, 2019

दिव्यांग लोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उन्हें मुख्यधारा में शामिल करने के उद्देश्य से हर साल 03 दिसंबर को 'विश्व दिव्यांग दिवस' मनाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 2.68 करोड़ दिव्यांग लोग हैं, जो देश की कुल आबादी का लगभग 2.21 प्रतिशत है। एक समय था, जब दिव्यांगता को खुद दिव्यांग व्यक्ति और उसके परिवार के लिए अभिशाप और बोझ माना जाता था। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने ऐसी धारणा को खत्म कर दिया है। आज सामाजिक सोच में बदलाव आया है। दिव्यांग व्यक्ति के साथ अब समाज से बहिष्कृतों की तरह व्यवहार नहीं किया जाता। उन्हें समाज में अधिक स्वीकार्यता मिल रही है।

मोदी सरकार ने दिव्यांगजनों के जीवन को सहज और बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उनकी शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए नए उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। सुगम्य भारत अभियान के जरिए दिव्यांगों की सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा दिया गया है। उन्हें गरिमामय जीवन व्यतीत करने के लिए कानूनी और संस्थागत उपाय के साथ ही कौशल विकास, समान अवसर एवं सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। छात्रवृत्तियां और वित्तीय सहयोग प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। उन्हें समाज एवं राष्ट्र के अभिन्न एवं महत्वपूर्ण घटक के रूप में देखा जाने लगा है, जिससे उनमें आत्मविश्वास पैदा हुआ है। दिव्यांग भी अब जीवन के सभी क्षेत्रों और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। मोदी सरकार उनकी जरूरतों को लेकर काफी सजग है। इसलिए नए अनुसंधान और तकनीकी विकास पर जोर दे रही है, ताकि उनके जीवन को अधिक गतिशील और उत्पादक बनाया जा सके।

दिव्यांगों के प्रति संवेदनशील प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दिव्यांगों के प्रति काफी संवेदनशील हैं। वह देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने दिव्यांगता के मुद्दे को जन सामान्य के चिंतन का विषय बनाया। दिव्यांगों को मुख्यधारा में लाने के लिए अपने आचरण से भी लोगों को प्रेरित किया। पीएम मोदी ने 'मन की बात' कार्यक्रम में दिव्यांगों की विशेष क्षमता और स्थिति के कारण पहली बार उनको 'दिव्यांग' संबोधित किया। मई 2014 में केंद्र की सत्ता में आने के बाद उन्होंने दिव्यांगों के जीवन को सहज बनाने और उनमें आत्मविश्वास पैदा करने के लिए कई ऐतिहासिक फैसले किए। आजादी के 70 साल के बाद पीएम मोदी ने सभी दिव्यांगों के लिए एक साइन लैंग्वेज सिखाने की व्यवस्था की। उनके लिए 'अशक्त मित्र राज्य' बनाने की अनोखी पहल की। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह उनको न्याय दिलाने के लिए मार्गदर्शन दिया है, उससे दिव्यांगों के प्रति नवचेतना पैदा हुई है।

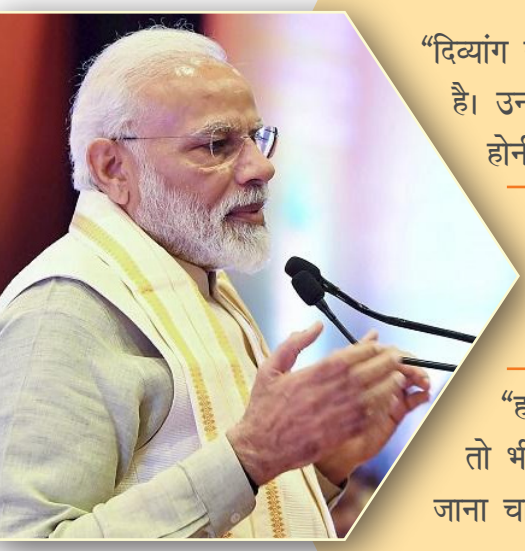

"दिव्यांग समग्र समाज, समस्त देश का दायित्व होता है। उनके लिए हम सभी के मन में संवेदनाएं होनी चाहिए।"

"हमारे समाज की सोच में बदलाव आना चाहिए, इसके लिए समाज का एक कैरेक्टर बने, जिसमें दिव्यांगों के लिए भी जगह हो।"

"हम घर बनाएं तो भी, या कोई भी कार्य करें तो भी दिव्यांगों की सुविधाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए।"

दिव्यांगों से आत्मीय रिश्ता

प्रधानमंत्री मोदी का दिव्यागों के प्रति लगाव किसी से छुपा नहीं है। केरल के बिना हाथों के पैदा हुए दिव्यांग मोहम्मद असीम को मदद देने का मामला हो, वाराणसी में हवाई अड्डे पर दिव्यांग को गले लगाना हो या गुजरात में भीड़ में खड़े एक दिव्यांग से हाल-चाल पूछना हो। ऐसे कई मिसाल है, जिनसे पता चलता है कि पीएम मोदी को जब भी मौका मिला, उन्होंने दिव्यांगों के साथ आत्मीय रिश्ता कायम की।

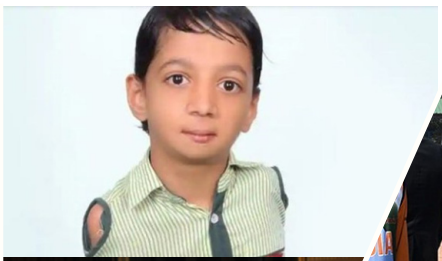

दिव्यांगों के लिए समर्पित मोदी सरकार

मोदी सरकार ने बड़ी संख्या में हाशिए पर खड़े दिव्यांगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की और उनके कल्याण और पुनर्वास के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम शुरू किए गए-

सामाजिक सबलता

- मोदी सरकार ने 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016' को पारित किया, जिसे अप्रैल 2017 में लागू किया गया।
- इस कानून में दिव्यांगता से संबंधित सभी तरह के भेदभाव पर रोक लगाने का प्रावधान किया गया।
- सामाजिक सशक्तीकरण के लिए व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामुदायिक और नीतियों के स्तर पर प्रयास तेज किए गए।
- 1992 से 2013 तक एडीआईपी योजना के तहत 55 शिविर लगाए गए।
- 2014 से दिसंबर 2018 तक देश में 7745 शिविरों के माध्यम से 12.23 लाख दिव्यांगों को लाभ पहुंचा।
- मोदी सरकार ने दिव्यांगता की श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया, ताकि अधिक दिव्यांगों को लाभ मिल सके।
- पहली बार स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी को जोड़ा गया।

आर्थिक विकास

- 1999 में राष्ट्रीय न्यास को 100 करोड़ की सीमित धनराशि दी गई। जिसमें बढ़ोत्तरी पीएम मोदी के शासन में हुई।
- 15 वर्षों में योजनाओं पर प्रति वर्ष 4.31 करोड़ रुपए ही खर्च हो पा रहे थे।
- वर्ष 2013-14 में 95.36 करोड़ रुपए के बजट को बढ़ाकर 2018-19 के लिए दोगुने से ज्यादा 220 करोड़ कर दिया गया।
- प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर राष्ट्रीय न्यास को एक नया स्वरूप देने की कोशिश की गई।
- दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना के तहत दिव्यांगों के पुनर्वास से जुड़ी परियोजनाओं को वित्तीय मदद दी जाती है।

शारीरिक स्वावलंबन

- दिव्यांगों को मनोचिकित्सा, फीजियोथेरेपी, सर्जिकल सुधार, स्पीच थेरेपी सुविधा दी जा रही है।
- 29 राज्यों में 416 मैगा कैंप या विशेष कैंपो के माध्यम से सहायक यंत्रों और उपकरणों का वितरण किया गया।
- बच्चों के कोकलियर इंप्लांट सर्जरी के लिए देशभर में 172 अस्पतालों को पैनलबद्ध किया गया।
- पिछले 5 वर्षों में 80 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगजनों को मोटर चालित तिपहिया साइकिल दी गई।
- दिव्यांगों के लिए मोटर चालित तिपहिया साइकिल की पात्रता उम्र 18 साल से घटाकर 16 वर्ष की गई।
- दिव्यांग के हाथ में सेंसर युक्त आधुनिक छड़ी दी गई, ताकि वे सामने आने वाली बाधाओं से अपना बचाव कर सके।
- मोदी सरकार ने दिल्ली के ओखला में भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की।
- जुलाई 2018 में दिव्यांगों के लिए 3000 शब्दों का एक शब्दकोश 'दि इंडियन साइन लैंग्वेज' लॉन्च किया गया।
- राज्य स्तर पर स्पाइनल इंजूरी केंद्रों की स्थापना की गई, साथ ही जिलों में 12 बेड वाले पुनर्वास केंद्र स्थापित किए गए।

मोदी राज में बने विश्व रिकॉर्ड

5 नवंबर, 2016 को मणिपुर शिवर में 8 घंटों में 3911 दिव्यांगों को श्रवण यंत्र फिट कर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया।	गुजरात के राजकोट में एक दिन में 781 दिव्यांगों को केलिपर्स फिट कर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया।	28 फरवरी, 2019 को गुजरात के भरूच में 8 घंटे में 260 दिव्यांगजनों को प्रोस्थेटिक अंग फिट कर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया।

नई योजनाएं और कार्यक्रम

24 नवंबर, 2015 को नेशनल ट्रस्ट के तहत दिव्यांगों के लिए 10 नई योजनाओं की घोषणा की गई-

दिशा	0-10 साल तक के बच्चों की देखभाल और स्कूल चलो अभियान
विकास	10 साल से ऊपर के दिव्यांगों की दिवसीय देखभाल (डे केयर)
समर्थ	राहत कार्यों की देखभाल
घरौंदा	व्यस्क दिव्यांगों के लिए सामूहिक घर
निरामय	स्वास्थ्य बीमा योजना
सहयोगी	देखभाल के लिए प्रशिक्षण योजना
ज्ञान प्रभा	शैक्षिक समर्थन
प्रेरणा	विपणन सहायता
समभाव	एड्स पीड़ितों के प्रति समभाव
बढ़ते कदम	जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता

दिव्यांग महिलाओं का सशक्तीकरण

- दिव्यांगों की कुल आबादी में 42.46 प्रतिशत दिव्यांग महिला है। मोदी सरकार उनको विशेष सुविधाएं दे रही हैं।
- महिला दिव्यांगों की विशेष शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया जा रहा है, ताकि रोजगार के अवसर उपलब्ध हो।
- छोड़ी गई दिव्यांग महिलाओं के पुनर्वास के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

दिव्यांगों के लिए खास सिक्के

- मोदी सरकार ने मार्च 2019 में दिव्यांगों की सुविधा के लिए पहली बार 20 रुपये का सिक्का जारी किया।
- इसके अलावा 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के नए सिक्के भी जारी किए गए।
- ये सिक्के दिव्यांगों के लिए खास है, क्योंकि इन सिक्कों को वे आसानी से पहचान सकते हैं।

दिव्यांगों की पहुंच में दुनिया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 3 दिसंबर, 2015 को सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत की। यह अभियान सामुदायिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दिव्यांगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

निर्माण परिवेश

- सार्वजनिक भवनों और स्थलों पर सुगम्यता को बढ़ावा
- सार्वजनिक भवनों में रैम्प की व्यवस्था
- सुगम्य पार्किंग की व्यवस्था
- सुगम्य शौचालय की व्यवस्था
- लिफ्ट में ब्रेल संकेतक और श्रव्य सिग्नल की व्यवस्था
- आपात समय में खाली कराने के लिए सुरक्षित उपाय

जुलाई 2022 तक 50 प्रतिशत सरकारी भवनों का सुगम्य लेखांकन और सुगम्य करने का लक्ष्य

31 दिसंबर, 2018 तक राज्यों में 1662 भवनों की सुगम्य लेखा परीक्षा पूरी की गई।

सुगम्य भारत अभियान
सुगम्य भारत - सशक्त भारत

PERFORM INDIA
National Movement for Developed India

सार्वजनिक परिवहन की सुगम्यता

- सुगम्य रेलवे स्टेशन, ट्रेन के डिब्बे और शौचालय
- सुगम्य मेट्रो ट्रेनों, बस स्टापों और बसों की व्यवस्था
- ट्रैफिक लाइटों पर श्रव्य संकेतक
- सुगम्य एयरपोर्टों और एयर कैरियर्स की अनुकूलता

अब तक 644 रेलवे स्टेशनों और 12,894 बसों को ऐक्सेसिबिलिटी फीचर से लैस किया गया है।

सभी 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 48 डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर दिव्यांगों के लिए आवश्यक सुविधाओं के प्रबंध किए गए, जैसे रैम्प्स, ऐक्सेसिबल टॉयलेट्स, ब्रेल सिंबल और ऑडिटरी सिगनल्स की व्यवस्था।

दिल्ली मेट्रो के 1100 कर्मचारियों को साइन लैंग्वेज में प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है। 30 नवंबर, 2018 तक साइन लैंग्वेज में 700 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी

- सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं की सुगम्यता
- सुगम्य प्रारूप में सूचना की उपलब्धता
- सुगम्य वेबसाइट और सार्वजनिक दस्तावेज
- नेत्रहीनों के लिए स्क्रीन रीडर प्रोग्राम

केंद्र सरकार की 100 वेबसाइटों को सुगम्य बनाने का लक्ष्य है, जिसमें 94 वेबसाइटों को सुगम्य बनाया जा चुका है।

सुगम्य भारत अभियान

सुगम्य भारत - सशक्त भारत

PERFORM INDIA
National Movement for Developed India

दिव्यांगों की पहुंच में टीवी कार्यक्रम

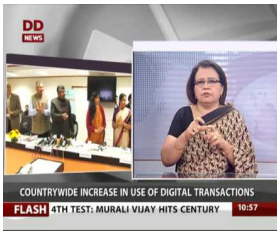

- साइन लैंग्वेज में टेलीविजन समाचार और 25 प्रतिशत सरकारी टीवी कार्यक्रम तय मानकों के अनुरूप
- 15 अगस्त, 2019 से निजी टीवी चौनलों पर दिव्यांगों के लिए साइन लैंग्वेज में लघु कार्यक्रम
- निजी टीवी चौनलों पर हफ्ते में एक बार साइन लैंग्वेज में न्यूज बुलेटिन की शुरूआत

सुगम्यता सूचकांक

- 30 मार्च, 2016 को दिल्ली के विज्ञान भवन में समावेशी और सुगम्यता सूचकांक का शुभारंभ किया गया।
- यह सूचकांक किसी संगठन में दिव्यांग सुगम्यता की मौजूदा स्तर का मूल्यांकन और मार्गदर्शन करता है।
- यह संगठनों के बेहतर व्यवस्था के लिए एक कसौटी है, जिससे दिव्यांगों के लिए सुगम्यता बढ़ाने का रास्ता तैयार होता है।

दिव्यांगों के लिए अशक्त मित्र राज्य

- पीएम मोदी ने दिव्यांगों के लिए 'अशक्त मित्र राज्य' बनाने की अनोखी पहल की।
- 18 राज्यों को प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया और देश के 58 शहरों को भी दिव्यांगों के अनुकूल बनाने का फैसला किया गया।

सुगम्य भारत अभियान

सुगम्य भारत - सशक्त भारत

PERFORM INDIA
National Movement for Developed India

दिव्यांगों के अनुकूल स्मार्ट सिटी

- स्मार्ट सिटी का एआईसी के साथ सम्मिलित करना, ताकि उसे और अधिक सुगम्य बनाया जा सके।
- शहरी नियोजन में दिव्यांग लोगों की जरूरतों पर ध्यान देना और परिवहन व्यवस्था का दिव्यांगों के हिसाब से तैयार करना।

स्वच्छता अभियान से सुगम बना शौचालय

- 8 सितंबर, 2019 तक देश में 15 लाख सुगम्य व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण
- व्यक्तिगत शौचालयों को सुगम्य बनाने के लिए ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों को प्रोत्साहन
- ग्राम पंचायत में दिव्यांग व्यक्तियों की पहचान के लिए विशेष प्रयास
- शौचलायों के निर्माण या सुधार की योजना में दिव्यांग व्यक्तियों की भागीदारी
- सामग्री और सहायक उपकरण खरीदने के लिए दिव्यांग के परिवार को अतिरिक्त वित्तीय सहायता

तकनीकी विकास से राह आसान

दिव्यांग व्यक्तियों को बेहतर जीवन जीने में टेक्नोलॉजी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे वे अधिक समावेशी विकास की ओर अग्रसर है-

सूचनाओं का भंडार 'दिव्यांग सारथी'

- दिव्यांग सारथी वन डेस्टीनेशन ऐप है, जो कानून, रोजगार और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
- ऐप में टेक्स्ट-टू-वॉयस कन्वर्जन सॉफ्टवेयर भी है, जो लिखित जानकारी को ऑडियो फाइल में कन्वर्ट करता है।

डिजिटल इंडिया से पारदर्शिता

- स्कीम मैनेजमेंट सिस्टम का विकास
- इस सिस्टम से पारदर्शिता को मिला बढ़ावा
- एनजीओ को राशि का सिर्फ आनॅलाइन ट्रांसफर
- एनजीओ द्वारा योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन
- राष्ट्रीय न्यास के दफ्तर का चक्कर लगाने की समस्या खत्म
- आवश्यक दस्तावेजों की ऑनलाइन अपलोड की सुविधा उपलब्ध

Digital India
Power To Empower

टेक्नोलॉजी बनी सहारा

- केंद्र सरकार की मदद से आईआईटी, दिल्ली के कुछ इंजीनियर द्वारा खास बैसाखी 'फ्लैक्सक्रच' का विकास
- सामान्य छड़ी की जगह कंप्यूटर प्रॉसेसिंग कौशल सहित बैट ईकोलोकेशन जैसी नई तकनीक का विकास
- दिव्यांगों को सचेत करने मे वाइब्रेशन सिग्नल, हैप्टिक सिग्नल और साउंड अलार्म मददगार
- दिव्यांगों के लिए जीपीएस से लैस नेवीगेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल
- दृष्टि बाधितों के लिए वाई-फाई, एनएफसी, इंफ्रा रेड टेक्नोलॉजी और ब्लूटूथ का इस्तेमाल
- पढ़ने की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऑप्टिकल केरेक्टर रीडर का विकास
- पाठ्यपुस्तकों और अखबारों तक प्रत्यक्ष डिजिटल पहुंच कायम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

"स्कूल, कार्यालय और अन्य सार्वजनिक स्थान दिव्यांगों के लिए सुगम्य बनाने के लिए इनोवेशन चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, व्यवस्था चाहिए, संवेदनशीलता चाहिए। इस काम का बीड़ा उठाया है।"

शिक्षित दिव्यांग, सक्षम भारत

- दिव्यांगता की श्रेणी में आने वाले 6 से 18 वर्ष के विद्यार्थियों की मुफ्त शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित किया गया।
- सरकारी और सरकारी अनुदान पाने वाले शिक्षण संस्थानों में दिव्यांगों के लिए आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% किया गया।
- ऑटिज्म से परेशान छात्रों को घर से परीक्षा देने की सुविधा उपलब्ध करायी गई ।

दिव्यांगों को रोजगारपरक शिक्षा

- दिव्यांगों को रोजगारपरक शिक्षा देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोर्सों के नए प्रारूप की शुरुआत की गई।
- सुनने में परेशानी वाले छात्रों के लिए साइन लैंग्वेज में ही हर विषय पढ़ाने के लिए अलग कोर्स तैयार किया गया ।
- नेत्रहीन छात्रों को कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए कीबोर्ड में बदलाव किया गया, ताकि कंप्यूटर के क्षेत्र में रोजगार मिल सके।

दिव्यांगों का शैक्षिक सशक्तीकरण

- मोदी सरकार ने दिव्यांगों के लिए 1 अप्रैल, 2015 से उच्च श्रेणी शिक्षा छात्रवृत्ति शुरू की।
- 1 अप्रैल, 2018 से सभी छह छात्रवृत्तियों को एक समग्र योजना में सम्मिलित किया गया।
- प्री व पोस्ट मैट्रिक, उच्च श्रेणी शिक्षा में उपलब्ध कुल छात्रवृत्ति स्लॉट का 50% महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया।
- राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृति स्लॉट का 30 प्रतिशत महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किया गया।

शोध कार्य के लिए अतिरिक्त समय

- अप्रैल 2016 से दिव्यांग शोधार्थियों को एमफिल पूरा करने के लिए एक साल का अतिरिक्त समय दिया जा रहा है।
- पीएचडी डिग्री पूरा करने के लिए दो साल का अतिरिक्त समय दिया जा रहा है।

दिव्यांगों को फ्री कोचिंग की सुविधा

- मोदी सरकार ने 1 अप्रैल, 2017 से दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए फ्री कोचिंग की सुविधा शुरू की।
- सार्वजनिक क्षेत्र की भर्ती परीक्षाओं और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षाओं के लिए फ्री कोचिंग की सुविधा उपलब्ध है।

कुशल दिव्यांग, अवसर अपार

दिव्यांगों के आरक्षण में वृद्धि

- मोदी सरकार ने सरकारी नौकरियों में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत किया।
- सीधी भर्ती वाली सरकारी नौकरियों में दिव्यांग युवकों को उम्र में 10 साल तक की छूट दी गई।

निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर

- मोदी सरकार ने दिव्यांगों को नौकरी देने वाली निजी कंपनियों को लुभाने की एक नई योजना शुरू की।
- निजी कंपनियों को दिव्यांगों के PF और ESIC में 10 साल तक कोई अंशदान नहीं देना होगा। इसका भुगतान सरकार करेगी।
- पिछले 5 वर्षों में निजी क्षेत्र की कंपनियों में दिव्यांगों के लिए रोजगार के मौकों में सुधार आया है।
- बड़े शहरों में कंपनियां दिव्यांगों को नियुक्त करने में बिजनेस वैल्यू देख रही हैं।
- बेहतर काम करके विकलांगों ने कंपनियों के साथ जो भरोसा बनाया है, उसका उन्हें फायदा भी हुआ है।

दिव्यांगों का कौशल विकास

- 21 मार्च, 2015 को दिव्यांगों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की गई।
- प्रधानमंत्री मोदी ने 38 लाख दिव्यांगों को लक्ष्य बनाकर राष्ट्रीय कौशल नीति पेश की।
- दिव्यांगों के लिए कौशल परिषद (ScPWD) बनायी गयी है, जो कौशल नीति तैयार करती है।
- 31 अक्टूबर, 2019 तक दिव्यांगों को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए 266 संगठनों को सूचीबद्ध किया गया।
- दिव्यांगों के काशौल विकास और राजेगार दिलाने में सलाहकार और मनोविकित्सक का सहयोग भी शामिल है।
- 600 से ज्यादा ग्रामीण स्वरोजगार संस्थानों के माध्यम से स्वरोजगार प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- कृषि और कुटीर उद्योगों से संबंधित कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर जोर दिया जा रहा है।
- प्रशिक्षण के लिए देश के 310 जिलों की पहचान की गई, जहां 262 जिला दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्र बनाए जाएंगे।
- दिव्यांगों द्वारा निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है।

जॉब पोर्टल और जॉब फेयर

- 27 जनवरी, 2016 को दिव्यांगों को रोजगार में मदद देने के लिए एक जॉब पोर्टल शुरू किया गया।
- मोदी सरकार ने दिव्यांगों के लिए जॉब फेयर आयोजित करने की शुरुआत की।

दिव्यांग खिलाड़ियों के जज्बे को सलाम

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दिव्यांग खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने का कोई मौका नहीं चूकते। जुलाई 2018 में 'मन की बात' कार्यक्रम में उन्होंने फिनलैंड में आयोजित जूनियर अंडर-20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाली हिमा दास के साथ ही ट्यूनीशिया में आयोजित विश्व पैराएथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली एकता भयान का जिक्र किया। 26 फरवरी, 2017 को अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में ब्लाइंड टी-20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने पर दिव्यांग खिलाड़ियों को बधाई दी।

"दिव्यांग भाई-बहन सामर्थ्यवान होते हैं, दृढ़-निश्चयी होते हैं, साहसिक होते हैं, संकल्पवान होते हैं। हर पल हमें उनसे कुछ-न-कुछ सीखने को मिल सकता है।"

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रियो पैरालंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की।

फरवरी 2018 में ब्लाइंड क्रिकेट विश्वकप जीतने वाली भारतीय टीम से मुलाकात कर पीएम मोदी ने जीत की बधाई दी।

दिव्यांग खिलाड़ियों की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए मोदी सरकार ने कई कदम उठाए हैं-

- सरकार ने फरवरी 2019 में देश में पांच दिव्यांग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की मंजूरी दी।
- ये खेल केंद्र मेघालय, ग्वालियर, चंडीगढ़, जीरकपुर (पंजाब) और विशाखापट्टनम में बनाये जा रहे हैं।
- इन केंद्रों पर विश्व के अग्रणी देशों के बराबर आधुनिक प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।

उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

- हर साल 03 दिसंबर को दिव्यांगों के सशक्तीकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है।
- वर्ष 2019 के लिए दिव्यांगजन सशक्तीकरण के लिए 14 श्रेणियों के तहत राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं।

National Disability Awards

दिव्यांगों का बेहतर भविष्य

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिव्यांगों के भविष्य को खुशहाल बनाने के लिए इनोवेशन और तकनीकी विकास पर जोर दिया है-

- प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज स्टार्टअप के तहत इनोवेशन को मौका दिया जा रहा है।
- अगर हमारे देश के युवा चाहें तो दिव्यांगों के लिए नये इनोवेशन कर सकते हैं।
- दिव्यांगों से संबंधित एक बड़ा बाजार है। ये बाजार न सिर्फ हमारे देश में है बल्कि विदेश में भी है।
- दिव्यांगों को सक्षम बनाने और उनकी परेशानियों को कम करने में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 ने दिव्यांगों के अधिकारों और हकदारियों की सीमाओं का विस्तार किया है।

दिव्यांगता के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है।

दिव्यांगों को बेहतर सुविधा देने के लिए नवंबर, 2018 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया।